



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, १० जनवरी, १९९७/२० पौष, १९१८

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

विधायी (अंग्रेजी) शाखा

अधिसूचना

शिमला-२, १० जनवरी, १९९७

संख्या एल०एल०आर०डी०(६) ३५/९६.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ८ जनवरी, १९९७ को प्रख्यापित हिमाचल

प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का अध्यादेश संख्यांक 2) को, संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके प्राधिकृत पाठ सहित, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-  
सचिव (विधि) ।

## हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1997

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 13) का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

भारत गणराज्य के सैतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

1. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, संक्षिप्त नाम। 1997 है।

1994 का 13

2. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 की उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

धारा 10 का संशोधन।

“(3) नगरपालिका में इस धारा के अधीन सीधे निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों के अतिरिक्त, पूर्णतः या अंशतः नगरपालिका क्षेत्र में समाविष्ट निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य विधान सभा के सदस्य, भी सदस्य होंगे और राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को भी, जो तीन से अधिक नहीं होंगे, सदस्य के रूप में नाम निर्देशित कर सकेगी:

परन्तु इस उप-धारा में निर्दिष्ट व्यक्तियों और नगरपालिका परिषद् की दशा में कार्यकारी अधिकारी तथा नगर पंचायत की दशा में सचिव को नगरपालिका की सभी बैठकों में उपस्थित होने तथा विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।”

3. मूल अधिनियम की धारा 211 में, उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

धारा 211 का संशोधन।

“(2) जहां निर्माण का स्वामी अपने बन्द किए गए कार्य या उस द्वारा पूर्ण किए गए कार्य के पश्चात् संशोधित रेखांक प्रस्तुत करता है और उसमें मंजूर रेखांक से विचलन है, तो नगरपालिका, उप-धारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विशेष या साधारण निदेशों के अधीन विचलन के मामलों का, मंजूर रेखांक से दस प्रतिशत तक प्रशमन कर सकेगी:

परन्तु जहां संशोधित रेखांक में—

- (i) किसी सरकारी भूमि या नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकरण में निहित भूमि; या
- (ii) किसी लोक सड़क, मार्ग, पथ या नाली को आच्छादित करते हुए; या
- (iii) हिमाचल प्रदेश सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण अधिनियम, 1969 के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए, निर्माण का परिनिर्माण अन्तर्वर्तित है—

1969 का  
21.

वहां नगरपालिका मंजूर रेखांक से विचलन का प्रशमन नहीं करेगी।

(2क) उप-धारा (2) के अधीन नगरपालिका के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, नगरपालिका द्वारा आदेश पारित करने से तीस दिन के भीतर और ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, उपायुक्त को अपील कर सकेगा।

(2ख) उप-धारा (2क) के अधीन अपील में उपायुक्त के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, उपायुक्त द्वारा किए गए आदेश से तीस दिन के भीतर और ऐसी विहित रीति में, राज्य सरकार को अपील कर सकेगा।

(2ग) अपील प्राधिकारी, कारणों को अभिलिखित करते हुए, उप-धाराएं (2क) और (2ख) में विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के पश्चात् भी अपीलें दाखिल करने की अनुज्ञा दे सकेगा और उक्त उप-धाराओं के अधीन तीस दिन की अवधि की संगणना करने के लिए आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की प्रमाणित प्रतियां उपाप्त करने के लिए व्यतीत हुआ समय अपवर्जित किया जाएगा।

(2घ) राज्य सरकार उप-धाराएं (2), (2क) और (2ख) में किसी बात के होते हुए भी, अत्यधिक कठिनाई के असाधारण मामलों में, मंजूर रेखांक से विचलन के मामलों का प्रशमन कर सकेगी।”

महावीर प्रसाद,  
राज्यपाल

शिमला:

तारीख: 8 जनवरी, 1997.

कुलदीप चन्द,  
सचिव (विधि)।

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

H. P. Ordinance No. 2 of 1997.

**THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT)  
ORDINANCE, 1997**

AN

**ORDINANCE**

*further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994).*

Promulgated by the Governor, of Himachal Pradesh in the Forty-seventh Year of the Republic of India.

Whereas the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Municipal- (Amendment) Ordinance, 1997.

Short title

2. For sub-section (3) of section 10 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (hereinafter called the principal Act), the following sub-section shall be substituted, namely:—

Amendment of section 10.

“(3) In a municipality, in addition to persons chosen by direct election under this section, the members of the State Legislature Assembly, representing constituencies which comprise wholly or partly in municipal area, shall also be the members and the State Government may, by notification, also nominate as members, not more than three, persons having special knowledge or experience of Municipal administration :

Provided that the persons referred to in this sub-section and the Executive Officer in case of Municipal Council and Secretary in the case of Nagar Panchayat, shall have the right to attend all the meetings of the municipality and to take part in discussion therein but shall not have the right to vote.”

3. In section 211 of the principal Act, for sub-section (2), the following sub-sections shall be substituted, namely:—

Amendment of section 211.

“(2) Where the owner of the building submits the revised plan, after the work has been stopped by him or the work is completed by him and there are deviations from the sanctioned plan, the municipality may, subject to the special or general directions of the State Government under sub-section (3), compound the cases of deviations upto 10% from the sanctioned plan :

Provided that where the revised plan involves erection of building—

- (i) on any Government land or the land vesting in a municipality or a local authority; or
- (ii) by covering any public road, street, path or drain; or
- (iii) by contravening the provisions of the Himachal Pradesh Roadside Land Control Act, 1969;

21 of 1969

the municipality shall not compound deviations from the sanctioned plan.

- (2A) Any person aggrieved by the decision of the municipality under sub-section (2), may within thirty days from the passing of the order by the municipality and in such manner as may be prescribed, appeal to the Deputy Commissioner.
- (2B) Any person aggrieved by the decision of the Deputy Commissioner in appeal under sub-section (2A), may, within thirty days from the order made by the Deputy Commissioner and in such manner prescribed, appeal to the State Government.
- (2C) The appellate authority may, for reasons to be recorded in writing, allow the appeals to be filed after the expiry of the period of thirty days specified in sub-sections (2A) and (2B) and for calculating the period of thirty days under the said sub-sections, the time spent in procuring the certified copies of the orders to be appealed against shall be excluded.
- (2D) Notwithstanding anything contained in sub-sections (2), (2A) and (2B), the State Government may, in exceptional cases of extreme hardship, compound the cases of deviations from sanctioned plans."